भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 5466

उत्तर देने की तारीख 25 मार्च, 2026 (बुधवार)

04 चैत्र, 1948 (शक)

प्रश्न

एनईएसआईडीएस-ओटीआरआई

5466. **श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः**

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शिलांग-तुरा सड़क के पूरा होने से यात्रा के समय को बारह घंटे से घटाकर छह घंटे करने में किस प्रकार सफलता मिली है;

(ख) उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना और सड़क के अन्यत्र अवसंरचना (एनईएसआईडीएस-ओटीआरआई) घटक के अंतर्गत मिजोरम के थेनजोल में 12 करोड़ रुपये की हेलीपोर्ट परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2026 तक त्रिपुरा की सभी ग्राम पंचायतों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक एकीकृत कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) फील्ड तकनीकी सहायता इकाई (एफटीएसयू) ने सड़क परियोजनाओं की भौतिक निगरानी में किस प्रकार सुधार किया है और उन्हें समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) मेघालय राज्य में शिलांग-नोंगस्टोइन-तुरा सड़क कोरिडोर के सुधार और चौड़ीकरण ने मौजूदासबस्टैंडर्ड स्ट्रेचेजको दो लेन कैरिजवे में पेव्ड शोल्डर्स के साथ एनएच-106 और एनएच-127बी के खण्डों को अपग्रेड करके यात्रा के समय को काफी कम कर दिया है। इससे पहले, कोरिडोर में संकीर्ण कैरिजवे, तेज मोड़, खड़ी ढलान और संकीर्ण पुल थे, जिसके कारण बार-बार भीड़भाड़ और वाहनों की आवाजाही धीमी गति से होती थी। सड़क के चौड़े होने और ज्यामितीय डिजाइन में सुधार की वजह से वाहन अब दोनों दिशाओं में सुचारू रूप से चल सकते हैं, जिससे औसत यात्रा गति बढ़ जाती है।

(ख) पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास स्कीम - अन्य सड़क अवसंरचना के अलावा (एनईएसआईडीएस-ओटीआरआई) के तहत "मिजोरम के थेनजॉल में हेलीपोर्ट और हेलीपैड का विकास" परियोजना को

13.10.2025 को 12.00 करोड़ रुपये की लागत के साथ मंजूरी दी गई थी। मिजोरम राज्य सरकार ने निष्पादन एजेंसी के चयन के लिए उक्त परियोजना के संबंध में निविदा जारी की है।

(ग) पंचायती राज मंत्रालय ने 14अगस्त, 2025 को एक एआई-इनेबल्ड वॉइस-टू-टेक्स्ट मीटिंग समेराइजेशन टूल, सभासार लॉन्च किया। सभासार प्लेटफॉर्म ग्राम सभा की कार्यवाही को संरचनावार कैप्चर करता है और उनका सारांश बनाता है तथा ग्राम सभा की बैठकों की आवृत्ति/प्रकार और भागीदारी जैसे प्रमुख मापदंडों की निगरानी करता है। त्रिपुरा सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभासार उपलब्ध कराया गया है और ग्राम पंचायतें नियमित ग्राम सभा और पंचायत बैठकों के लिए इसका उत्तरोत्तर उपयोग कर रही हैं।

प्रायोगिक कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, 15 अगस्त 2025 को त्रिपुरा की सभी 1,194 ग्राम पंचायतों को विशेष ग्राम सभाओं हेतु इस टूल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और 1,047 ग्राम पंचायतों ने उस दिन सफलतापूर्वक सभासार का उपयोग किया।

(घ)उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी और समय पर पूरा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने राज्य योजना विभागों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ सम्पर्क करने के लिए सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों में फील्ड लेवल टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (एफटीएसयू) को नियुक्त किया है ताकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय परियोजनाओं के डेटाबेस को बनाए रखा जा सके और अद्यतन किया जा सके, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं जिससे कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय को परियोजनाओं के निष्पादन के बारे में नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके और फीडबैक दिया जा सके। एफटीएसयू अन्य बातों के साथ-साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्कीमों के तहत सड़क परियोजनाओं सहित स्वीकृत परियोजनाओं का फील्ड निरीक्षण भी करती हैं।

इसके अलावा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं की समय-समय पर निगरानी और निरीक्षण किया जाता है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए परियोजना गुणवत्ता निगरानी/तृतीय पक्ष तकनीकी निरीक्षण एजेंसियां (पीक्यूएम/टीपीटीआई) लागू की गई हैं।

*****